POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2017/अंक 04

मासिक प्रेषण दि. 8 अप्रेल, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अप्रेल, 2017 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम ! राज्य विधान सभा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2017-18 का बजट रखा। बजट में ग्रामीण स्तर तक शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य व स्वच्छता, जैसी बुनियादी जरूरतों को अहमियत दी गई है।

बजट में इस बार मुख्य घोषणा पांच हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को स्मार्ट बनाने की है। इसके तहत गांवों में शहरों जैसी सुविधाओं का विस्तार करने का सपना संजोया गया है।

किसानों की बेहतरी व खेती की सेहत सुधारने, युवाओं के लिए 11 लाख रोजगार सृजन करने, बालिका शिक्षा व महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने और नागरिकों के हितों का खयाल रखने जैसे वादों को पूरा करने के लिए बजट में कई प्रावधान रखे गए हैं।

कुल मिलाकर बजट तभी अच्छा कहा जा सकेगा, जब घोषणाएं वास्तविक रूप से धरातल पर उतरें और उनका समय पर सही क्रियान्वयन हो। इसके लिए समय का निर्धारण और प्रशासनिक सुधार बेहद जरूरी है। नहीं तो यह बजट भी पुरानी कई घोषणाओं व योजनाओं की तरह कागजी पुलिन्दा बन कर रह जाएगा। जनता का पैसा जो राजकोष में आता है वह बेवजह खर्च नहीं हो, यह सुशासन का मूल मंत्र होना चाहिए।

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी लोकसभा में आम बजट प्रस्तुत किया। बजट में देश की आर्थिक सेहत को मजबूत बनाने, ग्रामीण विकास पर 25 फीसदी ज्यादा खर्च करने, जन-जन को घर का सपना दिखाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, तथा खेती और किसान के विकास को खास प्राथमिकता दी गई है।

पिछले दो सालों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह बढ़ाने का जो सिलसिला बन रहा है, वह एक अच्छा संकेत है। इस बार भी मनरेगा के लिए ज्यादा राशि का आवंटन किया गया है। लेकिन इसके माध्यम से पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बजट में भ्रष्टाचार व कालेधन के प्रवाह पर रोक लगाने के प्रयासों से सरकार की स्वच्छ छवि उभर कर सामने आई है।

कुल मिलाकर बजट में कई सुधार सामने आए हैं, जो देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने और बहुआयामी विकास को नई दिशा देंगे। आम ग्रामीण बजट के आंकड़ों को सही रूप से समझ नहीं पाता। इसलिए 'ग्राम गदर' में समय-समय पर गांवों से सम्बन्धित बजट घोषणाओं को सरल व तार्किक रूप में प्रकाशित किया जाता रहेगा, ताकि ग्रामीणजन इन घोषणाओं के सरकारी अमल पर पैनी नजर रख सकें और लाभान्वित हो सकें।

ग्रामीण क्षेत्र को दी ज्यादा सौगात

केन्द्र सरकार ने ग्रामीण विकास पर 25 फीसदी ज्यादा खर्च करने की तैयारी कर बजट में ग्रामीण क्षेत्र को ज्यादा अहमियत दी है। एक करोड़ गरीब परिवारों और 50 हजार ग्राम पंचायतों को 2019 तक गरीबी से बाहर लाने के लिए बजट में मिशन 'अंत्योदय' शुरू करने का ऐलान किया गया है।

पिछले बजट में मनरेगा के लिए 38 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान था जिसे बढ़ा कर 48 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट में घोषणा की है कि प्रदेश में पांच हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को स्मार्ट विलेज के तौर पर विकसित किया जाएगा। इन गांवों में परंपरागत व सौर ऊर्जा, स्ट्रीट लाइट, वाई-फाई, ई-लायब्रेरी, खेल मैदान, कचरा प्रबंधन, चारागाहों के विकास जैसी कई सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेगी।

किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान

केन्द्रीय बजट में कृषि ऋण लक्ष्य को एक लाख करोड़ रुपए बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 9 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। मृदा कार्ड को किसानों के लिए उपयोगी एवं लाभदायक बनाया जाएगा। कृषि क्षेत्र में मनरेगा योजना को नए तरीके से पेश किया जाएगा।

प्रदेश के बजट में खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 3156 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने की भी कई घोषणाएं की गई हैं। किसानों के लिए अनुदान 7500 करोड़ रुपए से बढ़कर 8500 करोड़ रुपए किया गया है। सीमान्त किसानों के लिए अनुदान 60 से 65 प्रतिशत और सामान्य किसानों का अनुदान 45 से 50 प्रतिशत किया गया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना शुरू की जाएगी। अगले दो साल में एक लाख नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। किसानों को बिजली की बढ़ी दरों को वापस लेकर राहत दी गई है।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

आवश्यक है डिजिटल युग में उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण

पूरा विश्व तेज गति से डिजिटल युग में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में हम सभी का दायित्व बनता है कि हर हालत में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण को अहमियत मिले और उनके अधिकारों की रक्षा हो।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में 'कट्स' द्वारा आयोजित 'उपभोक्ता के लिए डिजिटल दुनिया का निर्माण करना' विषयक गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए भावना शर्मा, सलाहकार, ट्राई, रीजनल ऑफिस, जयपुर ने यह विचार व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि सेवाप्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। डिजिटल उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए नियमन की जो व्यवस्था होगी वह सहज, सक्रिय, सामर्थ्यवान व कार्यक्षमता युक्त होगी। इसमें बदलाव की तेज गति अभी एक चुनौती है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में जॉर्ज चेरियन, निदेशक 'कट्स' ने कहा कि हर साल पूरे विश्व में 15 मार्च का दिन उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। डिजिटल युग में करोड़ों उपभोक्ता रोजाना इंटरनेट एवं मोबाइल के माध्यम से खरीददारी करते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है। उनके अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के उपाय बहुत जरूरी है।

मुहैया कराया जाएगा शुद्ध पेयजल

केंद्र सरकार के बजट के अनुसार गांवों में पेयजल लाइन का जाल बिछाया जाएगा। इससे पाइप लाइन से घरों तक पानी सप्लाई हो सकेगा। फ्लोराइड युक्त पानी का उपचार किया जाएगा। इसके लिए बजट में खास बढ़ोतरी की गई है।

पेयजल के लिए प्रदेश के बजट में पहली बार योजनाओं का दायरा बढ़ाया गया है। लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए गांवों में 1483 आरओ प्लांट लगाए जाएंगे। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों की 19 पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश की ढाई हजार ढ़ाणियों को पीने का साफ पानी मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत 4214 गांवों को शामिल किया जाएगा। अभियान के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नई तकनीक के जरिए अब स्वतः ही जलापूर्ति हो सकेगी। यह नवाचार जलापूर्ति में एक बड़ा बदलाव लाएगा। इसके लिए 120 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। जनता जल योजना को प्रभावी बनाया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास पर ध्यान

केंद्रीय बजट में महिलाओं को आर्थिक रूप से समर्थ बनाने के लिए 2.44 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। इसके जरिए जनजातियों, दलितों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को उद्योग लगा कर आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास होंगे।

बाल योजनाओं के संचालन पर 1.84 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। बालिकाओं और महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में महिला शक्ति केन्द्र बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता के तहत अब 6000 रुपए मिलेंगे। महिला सशक्तिकरण व संरक्षण के लिए 307 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। प्रदेश में इस बार भी बजट महिला दिवस पर रखा गया। इस दिन वसुंधरा राजे का जन्म दिन भी था। बजट में महिलाओं व बालिकाओं से संबंधित कई घोषणाएं सीधे तौर पर ग्रामीण स्तर पर फायदेमंद साबित होंगी। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अच्छी घोषणाएं की गई है। महिलाओं में जागृति लाने के लिए चिराली योजना लागू की जाएगी।

लघु उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

केन्द्र सरकार ने बजट में राजस्थान की कपड़ा और फुटवियर इंडस्ट्री को करों में छूट देकर प्रोत्साहित किया है। कपड़ा इंडस्ट्री को दिया गया 6000 करोड़ रुपए का बजट भीलवाड़ा स्थित सैंकड़ों इंडस्ट्रीज को लाभ पहुंचाएगा।

राज्य के बजट में पिछड़े व अत्यंत पिछड़े इलाकों में उद्योग लगाने पर अतिरिक्त लाभ दिए गए हैं। इसके लिए सरकार अब भूरूपांतरण शुल्क में 50 प्रतिशत के बजाय 100 प्रतिशत छूट देगी। रोजगार सृजन सब्सिडी की सीमा सामान्य कार्मिक व महिला, एससी, एसटी के लिए 10-10 हजार रुपए बढ़ा दी गई है। खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए 4 करोड़ 41 लाख रुपए का प्रावधान बजट में है।

मध्यम वर्ग को दी आयकर में राहत

केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आयकर की टैक्स स्लेब में बदलाव किया है। वित्तीय वर्ष 1997-98 से लगातार जारी 10, 20 व 30 प्रतिशत के स्लेब को बदल कर 5, 20 और 30 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे कम आमदनी वाले मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिली है।

स्लेब के मुताबिक 2 लाख 50 हजार रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं है। इसके बाद 2 लाख 50 हजार एक रुपए से 5 लाख रुपए पर अब 10 फीसदी की बजाय 5 फीसदी ही आयकर देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों को 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स देय नहीं है तथा 80 साल से अधिक उम्र के करदाता पर 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

स्वास्थ्य का पलड़ा-नब्ज पर हाथ

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में जन स्वास्थ्य पर खास जोर दिया है। देश में एक लाख 50 हजार स्वास्थ्य उपकेंद्रों का विकास किया जाएगा। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार कर उन्हें आधुनिक बनाया जाएगा। बजट में काला ज्वर, टीबी जैसी कई खतरनाक बीमारियों को खत्म करने पर जोर दिया गया है। बुजुर्गों का खास ध्यान रखने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा।

प्रदेश के बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 6315 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यह पिछले साल के मुकाबले 8.21 फीसदी ज्यादा है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र तक चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने का वादा किया है। अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। जयपुर में हार्ट ट्रांसप्लांट और कोटा में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा होगी।

देश को डिजिटल करने की कोशिश

केंद्र सरकार के बजट से ब्रॉडबैंड व डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। देश में ढांचागत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में दूरसंचार प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। ऑप्टिकल फाईबर का जाल बिछेगा। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से 1.50 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा।

पंचायतों के ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ने पर ग्रामीण इलाकों में ढांचागत सुविधाओं का विस्तार होगा इससे ग्रामीणों के सभी काम गांव में ही आसानी से हो जाएंगे। उन्हें बार-बार शहरों की ओर भागना नहीं पड़ेगा।

नोटबन्दी के बाद से डिजिटल भुगतान के तरीकों में भी तेजी से वृद्धि हुई है। बजट में मुद्रारहित अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश के बजट में इसके लिए डिजिटल राजस्थान की परिकल्पना की गई है।

गांवों में बिछेगा सड़कों का जाल

केन्द्र सरकार के बजट के मुताबिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वित्तीय वर्ष में 27 हजार करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का जाल बिछेगा। इसमें केन्द्र सरकार के 19 हजार करोड़ रुपए और शेष राशि राज्यों के अंशदान से मिलेगी। राजमार्गों के विकास पर 64 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।

प्रदेश के बजट के अनुसार राज्य में 2000 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ और मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही 800 करोड़ रुपए खर्च कर 5000 किलो मीटर ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण का काम किया जाएगा। राज्यमार्गों पर 796 किलो मीटर की 15 परियोजनाएं शुरू होंगी।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र
कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)
डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई-मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर